महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन अधिनियम

1st संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1951: इस संशोधन ने अनुच्छेद 15 (4) और अनुच्छेद 19 (6) को जोड़ा और मौलिक अधिकारों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में निजी संपत्ति के अधिकार में परिवर्तन लाया। संविधान की नौवीं अनुसूची को भी इससे जोड़ा गया।

7 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1956: इस संशोधन के माध्यम से राज्य पुनर्गठन अधिनियम के कार्यान्वयन को संभव बनाया गया था। भाग ए, भाग बी और भाग सी में राज्यों का वर्गीकरण इसके बाद बंद हो गया। राज्यसभा और संघ और राज्य विधानसभाओं में सीटों का पुन: विभाजन किया गया। इसने अतिरिक्त और अभिनय न्यायाधीशों, उच्च न्यायालयों और उनके न्यायालयों आदि की नियुक्ति के बारे में परिवर्तनों को भी प्रभावित किया.

13 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1962: नागालैंड राज्य के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए अनुच्छेद 371 ए को सम्मिलित करना.

14 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1962: पूर्व फ्रांसीसी क्षेत्रों पांडिचेरी, कराईकल, माहे और येनम को केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी (अब पुडुचेरी) के रूप में निर्दिष्ट किया गया था।

15 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1963: इसने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी। अनुच्छेद 226 के तहत सरकार या उसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर स्थित प्राधिकरण को रिट जारी करने के लिए एक उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाया। ऐसे क्षेत्राधिकार के भीतर कार्रवाई होती है.

19 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1966: निर्वाचन आयोग के कर्तव्यों को स्पष्ट करने के लिए अनुच्छेद 324 में संशोधन किया गया। इसने चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के चुनावी विवाद तय करने के लिए चुनाव न्यायाधिकरण नियुक्त करने की शक्ति से वंचित कर दिया.

21 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1967: आठवीं अनुसूची में सिंधी भाषा को 15 वीं क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया.

24 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1971: गोलक नाथ केस में निर्णय के प्रभाव को बेअसर करने के लिए संसद का प्रतिशोधात्मक कार्य था। इसने अनुच्छेद 368 और अनुच्छेद 13 में संशोधन करके मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की संसद की शक्ति की पुष्टि की.

26 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1971: इस संशोधन ने रियासतों के शासकों को मान्यता वापस ले ली और उनके प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया.

31 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1973: इस संशोधन द्वारा, लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गईं, लेकिन लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया.

39 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1975: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनावों के संबंध में विवाद या प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर किए गए थे.

42 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976 (मिनी संविधान): 42 वें संशोधन ने संवैधानिक संरचना में मूलभूत परिवर्तन किए और इसे शामिल किया गया।

प्रस्तावना में "समाजवादी", "धर्मनिरपेक्ष" और "अखंडता" शब्द। भाग IVA में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई थी और संसद द्वारा इस आशय का कोई भी कानून न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखा गया था। इसने संसद की शक्ति को अब तक सर्वोच्च बना दिया क्योंकि संविधान में संशोधन का संबंध था। इसने सर्वोच्च न्यायालय को कुछ मामलों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने और उच्च न्यायालयों के रिट क्षेत्राधिकार को फिर से परिभाषित करने के लिए अधिकृत किया। इसने केंद्र को सशक्त कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए किसी भी राज्य में सशस्त्र बलों को तैनात करने का अधिकार दिया। इसने राष्ट्रपति को देश के किसी भी हिस्से या पूरे भारत के लिए आपातकाल की घोषणा करने के लिए अधिकृत किया.

43 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1977: 43 वें संशोधन ने 42 वें संशोधन द्वारा डाले गए कई अनुच्छेदों को छोड़ दिया। इसने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को बहाल किया, जिसे 42 वें संशोधन के तहत हटा दिया गया था.

44 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1978: संशोधन को जनता पार्टी सरकार द्वारा लाया गया जिसने 42 वें संशोधन द्वारा प्रभावित कुछ परिवर्तनों को निरस्त कर दिया, कुछ को छोड़ दिया और परिवर्तन प्रदान किए। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से दूर ले जाया गया और एक सामान्य कानूनी अधिकार के रूप में एक नए अनुच्छेद 300 ए में रखा गया। राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में अनुच्छेद 352 में, शब्द 'आंतरिक गड़बड़ी' को सशस्त्र और विद्रोह शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था.

61 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1988: इसने 21 वर्ष की आयु से मतदान की आयु में कमी के लिए अनुच्छेद 326 में संशोधन किया.

69 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1991: अनुच्छेद 239 - AA और 239 - AB को एक विधान सभा और मंत्रिपरिषद के साथ केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पदनाम प्रदान करने के लिए संविधान में डाला गया था।

73 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992: पंचायती राज की संस्था को संवैधानिक गारंटी, दर्जा और वैधता प्राप्त हुई। इससे निपटने के लिए 11 वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें भाग IX भी सम्मिलित है, जिसमें अनुच्छेद 243, 243A से 243O शामिल हैं.

74 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992: भाग IX - A को सम्मिलित करके नगरपालिकाओं को संवैधानिक पवित्रता प्रदान करने के लिए, अनुच्छेद 243P से 243ZG और 12 वीं अनुसूची जिसमें नगर पालिकाओं से संबंधित वस्तुओं से संबंधित है.

86 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2002: अनुच्छेद 21 के बाद एक नया अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मौलिक अधिकार का अधिकार देता है। राज्य को निर्देशित करने के लिए अनुच्छेद 45 को स्थानापन्न करें ताकि छह वर्ष की आयु पूरी होने तक सभी बच्चों के लिए बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जा सके। संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 51 ए) में एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया।

88 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2003: इस संशोधन ने अनुच्छेद 268 के बाद एक नया अनुच्छेद 268A डाला, जिसने भारत संघ को सेवा कर लगाने का अधिकार दिया.

97 वाँ संवैधानिक संशोधन सभी 2011: अनुच्छेद 19 का संशोधन [भाग - III में, अनुच्छेद 19 में, खंड (एल) में, उप - खंड (ग) में, शब्दों या संघ के बाद, शब्दों या सह - सहकारी समितियों को सम्मिलित किया जाएगा]; भाग IV में नए अनुच्छेद 43B का सम्मिलन। ("43B: राज्य स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज लोकतांत्रिक नियंत्रण और सहकारी समितियों के पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।"

99 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2014: नए अनुच्छेद 124A, 124B और 124C की प्रविष्टि। अनुच्छेद 127, 128, 217, 222, 224 ए, 231 में संशोधन। संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रावधान करता है। 29 राज्यों (गोवा, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा सहित) से 16 राज्य विधानसभाओं ने केंद्रीय कानून की पुष्टि की, जिसने भारत के राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी सहमति देने में सक्षम बनाया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर, 2015 को, टोटो में संशोधन को रद्द कर दिया.

100 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2015: भारत द्वारा प्रदेशों के अधिग्रहण और बांग्लादेश को कुछ क्षेत्रों को हस्तांतरित करने के लिए भारत के संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन और भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर करने के परिणामस्वरूप एन्क्लेव के निवासियों को नागरिकता के अधिकार प्रदान करना। भारत और बांग्लादेश के बीच संधि।

101 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2016: छठे और सातवें अनुसूचियों के साथ, अनुच्छेद 248, 249, 250, 268, 269, 270, 271, 286, 366 और 368 में संशोधन किया गया है। अनुच्छेद 246 ए, 269 ए और 279 ए डाला जाता है जबकि अनुच्छेद 268 ए को छोड़ दिया गया है.
अनुच्छेद 246A[1] में जीएसटी के संबंध में विशेष प्रावधान हैं –

102 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2018: अनुच्छेद 338 बी, 342 ए और जोड़ा गया खंड 26 सी। अनुच्छेद का संशोधन 338, 366. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा।

103 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2019: धारा 15 (धारा 4) और (5) में उल्लिखित वर्गों के अलावा अन्य वर्गों के नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए अधिकतम 10% आरक्षण.

104 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2019: लोकसभा और राज्यों विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए सीटों के आरक्षण का विस्तार करने के लिए सत्तर साल से अस्सी साल तक। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को हटा दिया.

TEST SERIES
Bilingual
KVS PRT
30 TOTAL TESTS
Validity : 12 Months